तेल की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला

ध्यान रहे, पिछले करीब एक साल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। पिछले महीने यह तीन साल के शिखर 86 डॉलर प्रति बैरल को भी पार कर गया था।

मर्नाज शाह।।

तेल और गैस की ऊंची कीमतों से जूझते दुनिया के प्रमुख तेल उपभोक्ता देशों ने पूरे तालमेल के साथ अपने भंडार से तेल की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। अपनी तरह की इस पहली और अनोखी पहल का मकसद अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को नीचे लाना है। ध्यान रहे, पिछले करीब एक साल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। पिछले महीने यह तीन साल के शिखर 86 डॉलर प्रति बैरल को भी पार कर गया था।

भारत और अमेरिका समेत तमाम तेल उपभोक्ता देश तेल निर्यातक देशों के समूह ओपेक (ऑर्गनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज) से बार-बार तेल उत्पादन में मांग के अनुरूप बढ़ोतरी लाने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में अमेरिका, चीन, भारत, जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन जैसे देशों ने अपने भंडारों से तेल की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है।

गौर करने की बात है कि कोरोना महामारी के उथल-पुथल भरे इस दौर में एनर्जी मार्केट को असाधारण उतार-चढ़ावों से गुजरना पड़ा। लॉकडाउन जैसे कदमों के प्रभाव में एक समय उत्पादन संबंधी गतिविधियां ठप पड़ने से तेल की मांग में अभूतपूर्व कमी आ गई थी। उसके बाद धीरे-धीरे हालात बदले। लेकिन अब जब मांग महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच रही है, तेल सप्लाई उस अनुपात में नहीं बढ़ रही, जिससे न केवल इन देशों में पेट्रोल और गैस के भाव आसमान छू रहे हैं बल्कि आम लोगों को कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

भारत में भी बेलगाम हो रही पेट्रोल की कीमतों को कुछ हद तक नियंत्रित करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी लानी पड़ी, जिससे सरकारी खजाने पर करीब 60,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा। हालांकि, यह बात भी सच है कि भारत में हाल के वर्षों में इस पर एक्साइज ड्यूटी में काफी बढ़ोतरी हुई थी। असल में, तेल की ऊंची कीमतें न केवल महंगाई बढ़ा रही हैं बल्कि इस वजह से इकॉनमिक रिकवरी में भी मुश्किल हो रही है। अपने रिजर्व से तेल निकाल कर ओपेक देशों को उपयुक्त संदेश देने का यह फैसला इसी मजबूरी से निकला है।

हालांकि चाहे भारत के 3.8 करोड़ बैरल के भंडार में से 50 लाख बैरल निकालने की बात हो या अमेरिका के 60 करोड़ बैरल के भंडार में से 5 करोड़ बैरल निकालने की, यह मात्रा इतनी कम है कि इसका कोई और अर्थ नहीं लिया जा सकता। निश्चित रूप से यह एक सांकेतिक कदम है। अब देखने वाली बात यह है कि ओपेक देश इसे किस रूप में लेते हैं। उनकी अगली बैठक 2 दिसंबर को होनी है जिसमें वे जनवरी के लिए अपनी उत्पादन योजना को अंतिम रूप देंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि ओपेक तेल उपभोक्ता देशों के इस कदम को सही संदर्भों में लेते हुए इस पर पॉजिटिव ढंग से रिएक्ट करेगा।

स्वर्ग से बाहर

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

हम अन्याय सहने के बाद भी भोग की कामना से स्वर्ग के लिए लड़ाई लड़े और जीतने के बाद इंद्र आप की आराधना करके हमें उस जीते हुए स्वर्ग से बाहर कर दिए। हे माता! इस संसार में जो भी है वह आप के कारण है इसलिए आपको हम दोनों में भेदभाव करना शोभा नहीं देता।"

प्रहलाद की तर्कसंगत बातों को सुनकर देवी उनसे बोली हे दानवों! तुम सब लोग पाताल चले जाओ और वहां पर निर्भय होकर अपनी इच्छा अनुसार राज करो। अभी तुम लोगों को समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय ही अच्छे और बुरे का कारण बनता है। अभी तुम लोगों के लिए यही उचित है कि तुम लोग पाताल में जाकर सुख पूर्वक सुविधा पूर्वक राज करो। पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी से नीचे सात तल है, जिसमें सातवां तल पाताल है।

संपादकीय

फिर धीरे-धीरे जब ऐसा लगने लगा कि दुनिया वापस ढर्रे पर आ रही है, तो ओमिक्रॉन की आहट आने लगी। उसके चलते दोबारा कई तरह की रोक लगा दी गई है और टेंशन का माहौल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा।

पश्चिम से मध्य एशिया

हर्ष वी. पंत।।

इस साल इंटरनैशनल पॉलिटिक्स में काफी उथल-पुथल रही। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहा कि कोरोना से कैसे निजात मिले। यह साल एक तरह से कोरोना से शुरू होकर कोरोना पर ही खत्म हो रहा है। साल की शुरुआत में पहली और दूसरी लहर आई। फिर धीरे-धीरे जब ऐसा लगने लगा कि दुनिया वापस ढर्रे पर आ रही है, तो ओमिक्रॉन की आहट आने लगी। उसके चलते दोबारा कई तरह की रोक लगा दी गई है और टेंशन का माहौल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा।

कोविड सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं है। यह इकनॉमिक क्राइसिस भी है, वेल्थ क्राइसिस भी है। इस साल जो हेल्थ क्राइसिस से वेल्थ क्राइसिस बना था, उससे अभी तक दुनिया निकल नहीं पाई है। पहले ऐसा लग रहा था कि निकल जाएगी, पर ऐसा हो नहीं पाया। कोविड से जंग का कोई परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है। लग रहा है कि कोविड के साथ जीना दुनिया को सीखना पड़ेगा, यही न्यू नॉर्मल रहेगा। साल की शुरुआत में जो एक बड़ा डिवेलपमेंट रहा, वह ये कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ अमेरिका में एक राजनीतिक बदलाव आया। इससे उम्मीद थी कि कोई बहुत बड़ा नाटकीय परिवर्तन होगा, क्योंकि

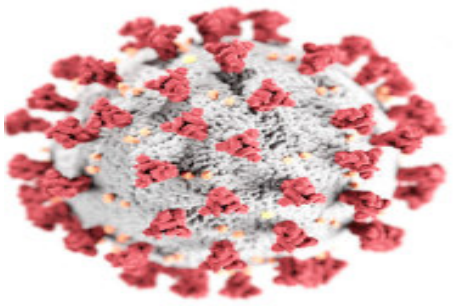

ट्रंप को कई लोग एक खास नजरिए से देखते थे। लेकिन गौर करें तो अमेरिकी विदेश नीति या अमेरिका के अंदरूनी माहौल में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा-बहुत बदलाव करने की कोशिश की है। लेकिन जो बड़े ट्रेंड्स हैं, मुद्दे हैं, चाहे वे विदेश नीति के हों या घरेलू नीति के, उसमें अगर आप उनका अंदरूनी हाल देखें तो पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। रिपब्लिकंस और डेमोक्रेट्स अभी भी काफी पोलराइज्ड हैं। एक्स्ट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के लोग अभी भी एक-दूसरे से बात करने को तैयार नहीं हैं। राजनीतिक समझौते नहीं हो रहे हैं।

ऐसे में जो बाइडन का अजेंडा अभी भी अटका हुआ है। इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान उनको कम करना पड़ा क्योंकि उन पर मॉडरेट्स का दबाव बना। विदेश नीति में उन्होंने ज्यादातर बातें ट्रंप की ही फॉलो की हैं। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने चीन पर और दबाव डालने की कोशिश की है। उसकी आर्थिक गतिविधियों पर कई और प्रतिबंध लगाए हैं। विंटर ओलिंपिक्स के बहिष्कार की घोषणा की। शिनजियांग और वीगर मुद्दे को लेकर काफी एक्सप्रेसिव बयान दिए। मानवाधिकारों के मामले में चीन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। अभी जो समिट ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसमें भी चीन को घेरा गया। मुझे लगता है कि दूसरा बड़ा ट्रेंड यह रहा कि अमेरिकी विदेश नीति का ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो रोल है, उसमें ट्रंप और बाइडन में ज्यादा बदलाव नहीं दिखा।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तीसरा बड़ा ट्रेंड हिंद प्रशांत क्षेत्र का रहा। हमने देखा कि कैसे दुनिया भर की राजनीति का केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण हिंद प्रशांत पर केंद्रित हुआ। अमेरिकी विदेश नीति हिंद प्रशांत पर केंद्रित है और चीन तो है ही यहां पर। तो जो भी बड़े बदलाव आ रहे हैं, बड़े विवाद चल रहे हैं, वे हिंद प्रशांत से जुड़े हैं। चाहे वे तकनीक के हों, सप्लाई चेन के हों, समुद्री सीमा सुरक्षा के हों, व्यापार के हों, या चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी से संबंधित हों। हिंद प्रशांत क्षेत्र में में जो बड़ा बदलाव आया है, वह अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड प्लेटफॉर्म है। इस साल क्वाड पुख्ता तरीके से खड़ा हुआ। दो समिट हुए, एक वर्चुअल, एक फिजिकल।

रूस-भारत संबंध

मध्य एशिया के जो पांच देश हैं, उनके साथ रूस भी इसे लेकर काफी परेशान है। मध्य एशिया और रूस के संबंधों ने जो गति पकड़ी है, अफगानिस्तान उसका बहुत बड़ा कारण है। वहां आतंकवाद और चरमपंथ के जोर पकड़ने के आसार हैं। फिर जिस तरह से शी जिनपिंग का दबदबा चीन में बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर भी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में चौथा ट्रेंड भी हिंद प्रशांत से ही जुड़ा हुआ नजर आता है। चीन में शी जिनपिंग का जो कंट्रोल है, वह लगभग पूरा हो गया है। इस बार पार्टी के समारोह में उन्होंने खुद को माओ की तुलना में खड़ा कर दिया। बाकी के पुराने नेता दूसरी श्रेणी में खड़े किए गए। एक तरह से उनके व्यक्तित्व का चीन में पंथ बन रहा है। इसे लेकर काफी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इसके चीन में क्या नकारात्मक प्रभाव होंगे और इनका चीन की विदेश नीति पर क्या प्रभाव होगा। इसके कुछ संकेत तो हमें अभी से देखने को मिल रहे हैं। चीन ने पड़ोसी देशों के साथ आक्रामक रुख अपनाया है। भारत के खिलाफ हिमालय में उसका रवैया इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। साउथ चाइना सी में उसका जैसा वुल्फ ओरिएंटेड सीन देखने को मिल रहा है वह भी गौर करने लायक है। ऐसे में अगले साल भी चीनी रुख में किसी तरह का बदलाव आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे में पूरी संभावना है कि मध्य और दक्षिण एशिया के देशों को साथ में काम करना पड़ेगा।

अष्टयोग-4905

7		5			6	
	35	3	27	1	28	
6		4		2		3
	26		40		34	
1	3		7	5		4
	27		41	4	29	5
4	3			6	1	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4904 का हल

6	1	4	7	2	5	3
5	35	3	27	1	28	7
7	4	5	2	3	6	1
3	31	2	37	7	34	6
1	3	6	7	5	2	4
2	27	1	41	4	29	5
4	3	7	5	6	1	2

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

चरमपंथी समूहों को भी मिला बूस्ट

मोहन। चीन को एक बड़ा संदेश दिया गया कि हिंद प्रशांत में बड़ी ताकतें एक साथ काम करने को तैयार हैं और छोटे देशों को एक साथ विकल्प देने को तैयार हैं। सबसे बड़ा घटनाक्रम इस साल आतंकवाद और चरमपंथ को लेकर हुआ है। जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई है, उससे शंकाएं बढ़ती जा रही हैं। अफगानिस्तान के लिए तो यह आपदा ही है। आम अफगानी इस सर्दियों में जिस तरह से परेशानियां झेल रहे हैं, उनके चलते बहुत ज्यादा समस्याएं खड़ी होंगी। तालिबान के आने से चरमपंथी समूहों को भी बूस्ट मिला है। दक्षिण एशिया सहित इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारी आशंकाएं फैली हैं। पाकिस्तान में हम इसका प्रभाव पहले ही देख रहे हैं कि किस तरह से चरमपंथी समूह अब सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान की सरकार उनके सामने घुटने टेक रही है।